भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3372

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अस्पतालों की प्रगति

3372. श्री तारिक अनवर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष अस्पतालों, औषधालयों, एकीकृत आयुष अस्पतालों और अन्य अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता और वास्तविक प्रगति का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आयुष सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और आयुष स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की है, यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का बिहार में विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करने, आयुष संस्थानों को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता या नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): एनएएम के अंतर्गत समर्थित आयुष अस्पतालों, औषधालयों और एकीकृत आयुष अस्पतालों की कार्यक्षमता सहित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करने के लिए, बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की अम्ब्रेला योजनाओं को शामिल करते हुए सात (7) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत 2025 में नीति आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' (एनएएम) का मूल्यांकन किया गया था। हाल ही में, 29 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इसका उद्देश्य एनएएम के तहत अवसंरचना के विकास, सेवा प्रदायगी, मानव संसाधन, डिजिटल एकीकरण, दवाओं की आपूर्ति और शासन तंत्र की प्रगति का आकलन करना था। इससे पहले भी, 1-2 मई 2025 को एनएएम कॉन्क्लेव और सितंबर 2025 में "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" पर विभागीय शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसी समीक्षाएं की गई थीं। इसके अलावा, एनएएम योजना की

विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत बैठकें, आवधिक समीक्षा बैठकें और केंद्रीय टीम द्वारा फील्ड दौरे भी किए जा रहे हैं।

(ग): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए बिहार में, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में, आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और आयुष संस्थानों को मजबूत करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, एनएएम के तहत, बिहार राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****